दिल्ली दुग्ध योजना खर्च को नियंत्रित करना

2488. **श्री कपिल सिब्बल:**
श्री राज मोहिन्दर सिंह:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना को हो रहे निरन्तर घाटे को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान में व्यय की विभिन्न मदों जैसे प्रबंध, वितरण, प्रशासन, प्रसंस्करण तथा क्रय आदि में होने वाले खर्च में कटौती करने के लिए संभावनाओं का पता लगाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किस-किस मद पर कितनी कटौती हो सकने की संभावनाओं का पता लगाया गया है; और

(घ) यदि इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई तो उसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (घ) दिल्ली दुग्ध योजना के लगातार घाटे का प्रमुख कारण यह है कि दूध के लागत मूल्य तथा बिक्री मूल्य के बीच भारी अन्तर है। इस समय, दिल्ली दुग्ध योजना के प्रसंस्कृत दूध का औसत लागत मूल्य (अप्रैल, 98 से जनवरी, 99 तक) 12.84 रुपए प्रति लीटर (पॉलीपैक में टॉड) तथा 11.59 रुपए प्रति लीटर (पॉलीपैक में डबल टॉड) है जबकि इसका विक्रय मूल्य क्रमश: 7 रुपए तथा 6 रुपए प्रति लीटर है जिसका निर्धारण सरकार ने सितम्बर, 1992 में किया गया था। मदर डेयरी द्वारा वह दूध (पॉलीपैक में टॉड) 13 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचा जा रहा है। इसके अलावा, घाटे की राशि को कम करने के लिए मंत्रालय तथा योजना द्वारा बराबर संभव प्रयास किए जाते है। दूध के लागत मूल्य को कम करने की संभावनाओं का बराबर पता लगाया जाता है। तथा इसका यथासंभव क्रियान्वयन किया जाता है। यह स्पष्ट है कि अधिक से अधिक यही दूध मदर डेयरी द्वारा बेची जा रही कीमत पर बेचा जाए तो योजना को घाटे की बजाय फायदा होगा।

Assistance by NCDC for Godowns/ Storages

2489. SHRI N. THALAVAI SUNDARAM: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the amount of financial assistance provided by the National Cooperative Development Corporation to various State during the last three years for construction of rural godowns/cold storages by Cooperative in those States;

(b) whether Government of Tamil Nadu has made any recommendations to NCDC for sanction of cold storages/rural godowns in that State; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) State-wise position of assistance provided by National Cooperative Development Corporation during last three years for construction of rural godowns and cold storages is indicated in the Statement (*See* below)

(b) and (c) NCDC has not received any new proposal from the Govt. of Tamil Nadu for setting up rural godown/cold storage since 1995-96.

Statement

Assistance Released by NCDC for Construction of Rural Godowns and Cold Storage in the Country during the last three Years

		1995-96	1996-97	1997-98
1.	*Rural Godown*			
1.	Andhra Pradesh	1.04	0.00	0.00
2.	Arunachal Pradesh	00.00	0.00	4.75
3.	Assam	13.75	1.10	0.00
4.	Bihar	484.55	4.69	0.00
5.	J & K	0.00	0.00	0.00
6.	Karnataka	125.18	217.89	378.87
7.	Madya Pradesh	67.22	45.41	91.63
8.	Maharashtra	0.00	0.00	55.48
9.	Manipur	0.00	208.50	0.00
10.	Meghalaya	6.86	0.00	2.98
11.	Mizoram	5.70	2.33	1.05
12.	Nagaland	17.53	8.55	0.00
13.	Orissa	51.53	10.67	7.65
14.	Punjab	6.81	0.00	50.10
15.	Tripura	2.81	0.00	0.00
16.	Tamil Nadu	0.32	0.00	0.00
17.	Uttar Pradesh	0.00	0.00	171.70
18.	West Bengal	181.94	345.61	49.99
	Total	1016.13	844.75	814.20